the Customs House where they have to pass through. I am glad that the liberalisation process has started as far as this part is concerned. But I would like to draw the attention of the hon. Minister to one specific point. Are those exporters of items which India produces best considered to be pride of India, or can we build an inspiration into the exporters? As he has himself said that from 28,000 crores, we may go up to 40,000 crores. I would like to know whether there is any scheme of the Government to encourage, or inspire the people to say that they are the best in the world and a pride of Indian products.

The other thing I would like to know is whether the defective goods, where he found that enquiries were necessary for their being sub-standard, were in handicrafts or in engineering goods and whether any specific action has been taken in that sector where the goods have not been found to be satisfactory.

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: Sir, we take full pride in the people who are doing well, and I think it would be premature for me at this stage to say anything because a new Import-Export Policy will be laid on the Table of the House tomorrow. I think the fact which the honourable Member has made, that people should get recognition as well, is taken care of. This is one of the reasons why we are encouraging people to have in-built quality controls and we are leaving them free. As far as the promotion of products which you mentioned is concerned, it does not pertain to this question, but we have the Trade Development Authority, we are having major promotions abroad and there, the best exporters we have for handicrafts and others are being encouraged and, with the best stalls in the world today, we are having exhibitions.

Now, the whole point here is about the complaints which are coming. There are so few complaints that there have been hardly 15 to 20 in the whole year. There may be one or two on agricultural products, may be one or two on handicraft products, but there is nothing very substantive really. We had some complaints on agricultural products, and these we are looking into in consultation with the other Ministries.

Export Potential of Export Processing Zones

*242. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI RAM NARESH YADAV:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to a study conducted by the Indian Institute of Foreign Trade, the export potential of India's six Export Processing Zones has remained untapped;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) what steps are being taken by Government to attract foreign investors and to stimulate the exports of these zones in the next two years;

(d) whether it is also a fact that sizeable investment has been made on the setting up of these zones; and

(e) if so, what is the total investment made and the value of exports made by the units in these zones during the years 1988-89?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Indian Institute of Foreign Trade in its study on "Free Trade Zones in selected developing countries" has noted that exports from the six Export Processing Zones during 1988-89 was Rs. 516 crores *i.e.* about 2.6 per cent of our total exports. The study has stated

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Naresh Yadav.

that the zones have a positive role to play in expanding net foreign exchange earnings from manufactured exports. To fully exploit their export potential, a number of suggestions have been made which *inter alia*, include improvement of infrastructure, standardization of value addition formula, stream-linging of procedures, setting up of a national authority for the zones and a more liberal incentive package.

(c) An exercise has been undertaken to review the working of the Export Processing Zones with a view to stimulate exports.

(d) and (e) The total investment made by the Government on the setting up of the six Export Processing Zones since inception is Rs. 93 crores. The exports made by six Export Processing Zones during 1988-89 amounts to Rs. 516.52 crores.

श्री राम नरेश यादव: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने, जो मैंने प्रश्न किया था, उसका उत्तर नहीं दिया है बल्कि उसमें कुछ और इंडियन फारेन ट्रेड की तरफ से जो ज़ोन बनाए गए हैं, उसके सबंध में आगे क्या किया जाएगा उसके बारे में आपने उल्लेख किया है । मेरा प्रश्न यह था कि जो इंडियन फारेन ट्रेड ज़ोन है, उसकी तरफ से जो उसकी क्षमता है, 6 ज़ोन्स के अंदर जिस तरह से एक्सपोर्ट करने की बात है उसकी, उसका उपयोग नहीं किया गया है सही ढंग से, उसका क्या कारण है और उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ? लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उसके सबंध में एक भी शब्द कहने की कोशिश नहीं की । इससे लगता है कि जान-बूझकर के उस चीज को छिपाने की कोशिश की जा रही है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके कारण क्या हैं, जिसके कारण उसकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है ? यह बात सही है कि जो उसमें पूंजी लगी हुई थी उससे अधिक 516 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई, लेकिन उसके साथ-साथ जो उसकी पूरी क्षमता है उसका जो उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसके कारण क्या हैं ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : सर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने यह जरूर कहा था कि एक्सपोर्ट ज़ोन जो हैं, उसमें काम ठीक से नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट और बढ़ने चाहिए और उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए थे । उसके साथ-साथ उन्होंने और मुल्कों के विषय में भी जैसे चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, साउथ कोरिया, उनके बारे में भी जो एक्सपोर्ट ज़ोन हैं, उसके बारे में जो स्टेटिस्टिकल इन्फारमेशन है, वह दी थी, लेकिन रिपोर्ट में और इससे ज्यादा नहीं था, खाली उन्होंने आकड़े दिए थे । अब इस वक्त जो आप एक्सपोर्ट जोन्स के विषय में बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात यह है कि जब परफारमेंस हम इन ज़ोन्स मे देखेंगे तो इसमें एक चीज़ हमें यह याद रखनी चाहिए कि एक्सपोर्ट ज़ोन जो होता है उसमें थोड़ा जो हम बेनिफिट दे रहे हैं, तो वह बेनिफिट जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर है उनको भी दे रहे हैं और छोटी छोटी तो बहुत कठिनाइयां हैं, उनको हम लोग हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है कि विदेशी कोई भी बड़ी कम्पनी यहां आने के लिए इस वास्ते तैयार नहीं है कि हम अपने जो एक्सपोर्ट ज़ोन्स हैं, अपनी डोमेस्टिक मार्किट उनके लिए नहीं खोलते । लेकिन जैसे चीन है, जो भी वहां एक्सपोर्ट ज़ोन है, कोई भी बड़ी कम्पनी वहां जाती है तो वहां वह 25 से 30 फीसदी अपने प्रोडक्ट्स चीन में भी बेच सकती है । हम लोग इस समय इन्सिस्ट कर रहे हैं कि जो भी इस वक्त आएगा 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट ज़ोन में, उसको पूरी चीज़ एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, इसलिए उसमें कठिनाई आ रही है । मगर आप इसमें यह देखिए तो कण्डला, सांताक्रूज़, नायड, मद्रास, माल्डा, कोचीन, जो 6 आपके एक्सपोर्ट ज़ोन इस वक्त हैं, वहां पर दोनों एक्सपोर्ट स्पीज़ एरियाज़ से भी हो रहे हैं और जनरल करंसी एरियाज़ के भी हो रहे हैं और पूरी सरकार का

जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त 90 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, जो आज जो सेल हो रही है 500–600 करोड़ रुपए की तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो हमें पूरा मिल रहा है, मगर एक्सपोर्ट जिस तरह से बढ़ाना चाहते थे, वह नहीं बढ़ रहा है ।

श्री राम नरेश यादव: महोदय, जहां तक उस स्टडी का सवाल है, रिकमडेशन का भी सवाल है, उसके संबध में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई ? उसमें यह भी है कि क्या इसेटिव दिए जाएंगे जिससे उनको निर्यात करने की दिशा में सुविधा हो सके और वे अधिक निर्यात कर सकें ? मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं ।

साथ ही साथ जो एक नेशनल जोन बनाने की बात की गई थी, उस ऐथोरिटी के संबंध में सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ? उसके साथ-साथ जो 2.5 परसेंट की दर से निर्यात किया जा रहा है उसके बारे में स्टडी में यह कहा गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उसे 5 फीसदी पर ले जाना चाहिए । तो सरकार की तरफ से उसे 5 फीसदी के स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार ने कार्यवाही की है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री अरुण कुमार नेहरू: : इसमें पूरा इप्लीकेशन देखना पड़ता है । जहां तक ढाई परसेंट से पांच परसेंट ले जाने की बात है, इसमें यह भी देखना पड़ता है कि जो भी इंसेंटिव हम दे रहे हैं वह जस्टीफाई करते हैं या नहीं । मैंने जो आपसे बात कही है, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है वह यह है कि कोई भी बड़ी कपनी जो एक्सपोर्ट ज़ोन में आएगी, वह चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट उनके लिए खोली जाए।

श्री सभापति: आप उस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : वह मैंने आपको बताया था कि उस पर हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, उस पर जब निर्णय लिया जाएगा तभी मैं आपको बता सकता हूं ।

SHRI SURESH KALMADI: Sir, the Minister just mentioned about the study made about the Export Promotion Zones in countries like Indonesia, Korea, Malaysia and Philippines. The World Bank Research Observer came to the conclusion that the EPZs in developing countries have a limited role in export promotion. Does the Indian Government subscribe to this view?

Also I will just mention that you will have got your money back, Rs. 100 crores of the Government. Besides Rs. 100 crores invested by the Government, the private sector also invested about Rs. 100 crores. So, on Rs. 200 crores your return is just Rs. 500 crores. That also became Rs. 500 crores this year. It was up to now Rs. 200 crores, Rs. 300 crores. The returns definitely are not at all commensurate with the investment made by the private sector and the Government. What exact steps, besides what you have already mentioned, would you be taking in the case of Santa Cruz? Besides the Electronic Zone, we have just set up the Gem and Jewellery Export Zone. So, what specific help are you going to give to boost up the new industry coming up there?

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: Sir, the hon. Member is quite right in his observation on the export zones. Now, Santa Cruz, unlike other zones, is only restricted to a few product ranges, and we would certainly consider expanding it into other areas also. But, as I think, the basic problem remains, and that problem we are trying to take up with other Ministries also. If you take the general industries as such, we have been liberalising consistently on export incentives. So, the difference between the EPZ and what you have, the domestic tariff area or regular industry is not very substantial. The only real benefit which has come in the

EPZ is that there is a single-window clearance for the project which is going to come in. But basically we have to examine it. After all, we are in international competition. If somebody from abroad is going to come to invest here, our terms have to match, if not be better than that of other countries. We have got severe competition from Indonesia, Singapore, Malaysia, Mauritius, even from China. So, we are re-examining the whole system. As things stand today our turn-over, I think, will be closer to Rs. 600 crores. It can go up to Rs. 700 crores, Rs. 800 crores. But the dramatic increases which we are looking for will come only if you open up the domestic market to these people. Otherwise, they are not willing to come at all. They have option of 7, 8 countries around you. That is what is happening at the moment.

MR. CHAIRMAN: He wants to know about export of gems.

SHRI SURESH KALMADI: I also mentioned about the World Bank Report which says that the Export Promotion Zones have a limited utility. Is it a fact? There is no point in further investing and wasting time on that.

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: Sir, the Export Zones, you know, are a reality. We have set them up. We have made investments in them. In fact, we have put up recently a new zone in Vizag. But the point is, in the changing environment we have also got to change with the time. The Export Zones or the success of these Zones will also depend on quick decisions that are required. We are examining them at our end.

MR. CHAIRMAN: He wants to export Indian gems.

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: We would love to export more. In fact, the export of gems has touched nearly Rs. 3,500 or 4,000 crores figure. With the scrapping of the Gold Control Order export of gold jewellery should go up and with that Santa Cruz will have enormous possibilities.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, some of the gems I can recommend for export.

MR. CHAIRMAN: I hope you are not referring to good gems here.

AN HON. MEMBER: Already some gems are away.

PROF. C. LAKSHMANNA: I would like to ask the hon. Minister whether this study of the Indian Institute of Foreign Trade was sponsored by the Government of India, Ministry of Commerce or it was a *suo-motu* study conducted by the Institute. I am asking this because this is very important. If it had been a study sponsored by the Commerce Ministry, then the exercise which is being undertaken becomes to some extent superfluous. If you look at the answer, they have recommended very important suggestions—improvement of infrastructure, standardisation of value-added formula, streamlining of procedures, setting up of national authorities for the zones and more liberal incentive packages. Last one, of course, is not within the scope of the Commerce Ministry. I realise that. That is within the scope of the Finance Ministry and they have their own compulsions. But for the rest of it, what is that additional exercise that has to be done? The entire thrust of the report has been only in terms of improving the potential and the exercise is also in the same direction. Therefore, I would like to know what is the need for additional exercise. Is it because what has been given as a report is not in full detail or is it only an action programme which is being exercised? I would like to know this from the Minister.

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: We do our total case study as to what is the world trade scenario in various countries and the study of the Institute of Foreign trade is more in terms of statistical data given by them. As I mentioned earlier, although they have said that progress of the EPZ was not satisfactory, there was no concrete suggestion made except for six or seven headings which I mentioned. So, it was more in terms of a passing re-

ference and they have referred to other countries also and have given more statistical data than anything else.

Kickbacks pertaining to Pepsi Project

*243. SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:†

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report about kickbacks in the multi-national Pepsi Project; if so, what are the facts thereof and follow up action taken in the matter; and

(b) whether it is a fact that the company has already spihoned-off its profits out of the country; if so, how much and what action has been taken as yet or is proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) News reports to this effect have come to Government's notice.

Various views have been expressed in respect of different aspects of this project. They are under the active consideration of the Government.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मैंने एक निश्चित प्रश्न पूछा था। मैं आशा करता था कि उसका निश्चित उत्तर दिया जाएगा। लेकिन मंत्री महोदय ने जो टालू मिक्चर पिलाया है, उससे सन्तोष नहीं होगा। मैं प्रश्न का एक हिस्सा और एक उत्तर का हिस्सा पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं उप-प्रश्न पूछूंगा।

श्री सभापति : बहुत छोटा सा प्रश्न है क्या पढ़ना है उसको ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Atal Bihari Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, आपके ध्यान में लाना जरूरी है। प्रश्न था कि क्या यह सच है कि इस कंपनी द्वारा अपने लाभों को पहले ही देश से बाहर भेज दिया गया है, यदि हां, तो कितनी राशि इस प्रकार विदेश भेजी गई है और अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

इसका उत्तर देखिए--इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। सरकार इन पर सक्रिय विचार कर रही है।

श्री सभापति : सक्रिय विचार हो रहा है, अब क्या निष्क्रिय विचार करें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीमन्, मैंने इसलिए पूछा था कि आरोप यह लगाया गया है कि पैप्सी कोला को लाइसेंस देने में गोलमाल हुआ है। अब सरकार ने यह भी नहीं कहा कि हुआ है, यह भी नहीं कहा कि नहीं हुआ है। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि वह जांच कर रही है। तो किस बात पर विचार हो रहा है, सक्रिय विचार किस बात पर हो रहा है? गोलमाल का जो आरोप लगाया गया है, उसका एक आधार है। 1988 में जब इस परियोजना को स्वीकृति दी गयी तो इसका खर्चा बहुत कम था, 22 करोड़ था, अब वह बढ़कर 75 करोड़ हो गया है। यह ठीक है कीमतें बढ़ी हैं, मूल्यों में वृद्धि हुई है। मगर तीन गुना खर्चा बढ़ जाना, इसका औचित्य क्या है ? इस तरह की और भी परियोजनाएं चल रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं प्रचार करना नहीं चाहता। पेप्सी कोला पोटेटो-चिप्स बना रही है, पाप कार्न बना रही है। इस तरह के खाद्य बनाने वाले और भी उद्योग हैं, उनके ऊपर कितनी लागत आयी है, इसके आंकड़े मेरे पास हैं, मैं उन्हें उद्धृत कर सकता हूं। लेकिन 75 करोड़ की वृद्धि यह बताती है कि दाल में कुछ काला है। **(व्यवधान)**